



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-02032020-216487
CG-DL-E-02032020-216487

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 825]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941

No. 825]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

का.आ. 899(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है;

और, भारत सरकार का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) तेल विपणन कंपनियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है), के माध्यम से कार्यान्वित पहल नामक एलपीजी की लाभ का सीधा अंतरण स्कीम (जिसे इसमें स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रहा है;

और, स्कीम के अधीन, एलपीजी सहायिका स्कीम के वर्तमान मानकों के अनुसार एलपीजी उपभोक्ताओं (जिन्हें इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) के बैंक खातों में जमा की जाती है;

और, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निश्चि से उपगत आवृत्ति व्यय अन्तर्वलित है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

- (1) स्कीम के अधीन फायदा लेने के इच्छुक व्यष्टिक से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए;
- (2) स्कीम के अधीन फायदा लेने का इच्छुक व्यक्ति, जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त

अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यष्टिक किसी भी आधार नामांकन केंद्र (केंद्र सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर आधार नामांकन के लिए जा सकते हैं;

(3) आधार के विनियम 12 विनियम (नामांकन और अद्यतन), 2016, के अनुसार मंत्रालय, से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है, और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा स्वंय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरी बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु व्यक्तियों का आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक स्कीम के अधीन फायदे निम्नलिखित दस्तावेजों को पेश करने के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को दिए जाएंगे :-

(क) यदि उसका नामांकन किया गया है, उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :-

(i) बैंक के पासबुक या डाक खाने की पासबुक, जिसमें फोटो लगा हो; या

(ii) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन कार्ड); या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरी द्वारा जारी चालन अनुज्ञासि; या

(ix) किसी शीर्ष नामे पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी पहचान का प्रमाण पत्र, जिस पर ऐसे व्यक्ति का फोटो लगा हो; या

(x) कोई अन्य दस्तावेज, जो मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; और

(ग) एक वचनबंध (कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार) कि वह किसी तेल विपणन कंपनी की अन्य उपभोक्ता संख्या के अधीन एलपीजी सहायिका प्राप्त नहीं कर रहा है।

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक ढंग से फायदा प्रदान करने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा जिससे इस स्कीम के अधीन लाभार्थियों के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन हिताधिकारियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक व्यवस्था अपनाई जाएगी, अर्थात्:-

(क) खराब अंगुली छाप गुणवत्ता के मामले में, आईआरआईएस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अधिप्रमाणन के लिए अपनाई जाएगी जिसके द्वारा मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निर्बाध रीति में फायदों के परिदान के लिए अंगुली छाप के साथ आईआरआईएस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) अंगुली छाप के माध्यम से बायोमीट्रिक्स अधिप्रमाणन या आईआरआईएस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल नहीं होने की दशा में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार एक पासवर्ड (ओ टी पी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) ऐसे अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमीट्रिक्स या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम बेस्ट वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वास्तविक आधार पत्र के आधार पर स्कीम के अधीन फायदे दिए जाएं जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड पाठक की आवश्यक व्यवस्था मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से की जाएगी।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम के अधीन किसी वास्तविक हितधारी को उसको देय फायदों से वंचित नहीं किया जाता है, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सीधा फायदा अंतरण (डीबीटी) मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी कार्यालय ज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन व्यवस्था अपनाएगा।

5. यह अधिसूचना, असम और मेघालय राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. पी-20019/53/2014-एलपीजी (खंड II)]

आशीष चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2020

S.O. 899(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Petroleum and Natural Gas in the Government of India (*hereinafter referred to as the Ministry*) is administering the Scheme of **Direct Benefit Transfer of LPG called PAHAL** (*hereinafter referred to as the Scheme*) implemented through the Oil Marketing Companies (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, under the Scheme, LPG subsidy in the form of direct cash transfer (*hereinafter referred to as the benefit*) is credited to the bank accounts of the LPG consumers (*hereinafter referred to as the beneficiaries*) as per the extant norms under the Scheme;

And, whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

- (1) An individual desirous of availing the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrollment, provided he/she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case of absence of any Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents :—

- (a) if he/she has enrolled, his/her Aadhaar Enrolment ID slip; and
- (b) any one of the following documents, namely :—
 - (i) Bank or Post Office Passbook with photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration Card; or
 - (v) Voter Identification Card; or
 - (vi) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act card; or
 - (vii) Kisan Photo Passbook; or
 - (viii) Driving License issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person, issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (x) any other documents as specified by the Ministry; and
- (c) an undertaking (as per the prescribed format provided by the Implementing Agencies) that he/she is not availing LPG subsidy under some other consumer number of any Oil Marketing Company:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Implementing Agencies for that purpose.

2. In order to provide benefit to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Ministry, through its Implementing Agencies, shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely :—
 - a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
 - b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
 - c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick

Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Ministry through its Implementing Agencies.

4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his/her due benefits, the Ministry through its Implementing Agencies shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer (DBT) Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administrations, except the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. P-20019/53/2014-LPG (Vol.II)]

ASHISH CHATTERJEE, Jt. Secy.